GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE
DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

RAJYA SABHA
STARRED QUESTION NO. 214
TO BE ANSWERED ON THE 5/8/2022

SPENDING ON AGRICULTURE

*214. SHRI K.R. SURESH REDDY:

Will the Minister of AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government is cognisant that in terms of Government spending on agriculture, India lags behind several low -income countries such as Malawi (18 per cent), Mali (12.4 per cent), Bhutan (12 per cent), Nepal (8 per cent) as well as upper-middle income countries such as Guyana (10.3 per cent) and China (9.6 per cent); and

(b) if so, the corrective steps that are proposed to be taken by Government in this regard?

ANSWER

MINISTER OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(SHRI NARENDRA SINGH TOMAR)

(a) & (b): A statement is laid on the Table of the house.

STATEMENT REFERRED TO IN REPLY TO PARTS (a) & (b) OF RAJYA SABHA STARRED QUESTION NO. 214 REGARDING SPENDING ON AGRICULTURE DUE FOR REPLY ON 05.08.2022.

(a) & (b): Though agriculture is a State subject, Central Government implements various schemes through various Ministries to support agriculture. The total annual budgetary allocation of the Ministry of Agriculture & Farmers Welfare and various other allied Ministries/Departments is quite substantial in proportion to total budget of the Government and contribute in a major way towards development of agriculture and allied sector. In addition, the budgetary allocation of all State / UT Governments on agriculture and allied sectors are also quite substantial. Further, there has been about five times increase in budget allocation of Ministry of Agriculture and Farmers Welfare alone from 27662.67 crore in 2013-14 to Rs. 1,32,513.62 crore in 2022-23.

******

भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न सं. 214

05 अगस्त, 2022 को उत्तरार्थ

विषय: कृषि पर व्यय

214. श्री के. आर. सुरेश रेड्डी:

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि कृषि पर सरकारी व्यय के संदर्भ में, भारत कम आय वाले कई देशों, जैसे मलावी (18 प्रतिशत), माली (12.4 प्रतिशत), भूटान (12 प्रतिशत), नेपाल (8 प्रतिशत) और साथ ही उच्च-मध्यम आय वाले देशों, जैसे गुयाना (10.3 प्रतिशत) और चीन (9.6 प्रतिशत) से पीछे है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) एवं (ख): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

राज्य सभा में दिनांक 05.08.2022 को उत्तरार्थ "कृषि पर व्यय" के संबंध में श्री के. आर. सुरेश रेड्डी द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 214 के भाग (क) और (ख) के संबंध में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख): हालांकि कृषि एक राज्य का विषय है, केंद्र सरकार कृषि को सहायता देने के लिए विभिन्न मंत्रालयों के माध्यम से विभिन्न स्कीमों का कार्यान्वयन करती है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और विभिन्न अन्य संबद्ध मंत्रालयों/विभागों का कुल वार्षिक बजटीय आवंटन सरकार के कुल बजट के अनुपात में काफी अधिक है और कृषि तथा संबद्ध क्षेत्र के विकास की दिशा में इसका प्रमुख योगदान है। इसके अलावा, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों पर सभी राज्य / संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों का बजटीय आवंटन भी पर्याप्त है। इसके अलावा, केवल कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के बजट आवंटन में लगभग पांच गुना वृद्धि हुई है जो वर्ष 2013-14 में 27662.67 करोड़ रूपये की तुलना में वर्ष 2022-23 में 1,32,513.62 करोड़ रूपये हो गया है।

******

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please. I am moving to Question No. 214. Shri K.R. Suresh Reddy.

SHRI K. R. SURESH REDDY: Mr. Deputy Chairman, Sir, if you look at the answer, यह मंत्री जी का रिप्लाई नहीं, बल्कि मंत्रालय का रिप्लाई है। My question was very specific. एग्रीकल्चर के ऊपर जो खर्चा कर रहे हैं, our neighbouring and less developed nations are spending much more than what we are spending. The reply was evasive. Nevertheless, my first supplementary to the hon. Minister is this. In supporting agricultural infrastructure, Telangana has been a role model for the nation.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please...

SHRI K.R. SURESH REDDY: Sir, this is related to the question.

The Government of India keeps suggesting that there should be change in the cropping pattern. Telangana was the first State to come forward, under the leadership of KCR*garu*, to bring in palm oil cultivation in a big way, an area where you are spending almost 18 billion dollars, on edible oil imports, to reduce taxes.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please, put your question.

SHRI K.R. SURESH REDDY: Sir, my question is, since we are doing palm oil cultivation in such a big way, what is the support that the Government of India would extend to the Telangana Government? That is my first supplementary.

श्री कैलाश चौधरी : माननीय उपसभापति जी, माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है, उसमें इन्होंने सवाल के जवाब की बात की है, मैं उसमें यही कहना चाहूंगा कि इन्होंने पास-पड़ोस के देशों के बजट ऐलोकेशन की जो बात की है, मुझे इसमें यह बताते हुए प्रसन्नता है कि भारत सरकार का बजट लगातार बढ़ रहा है। 2013-14 में जो 27 हजार करोड़ रुपये का बजट था, वह बढ़कर 1 लाख 32 हजार करोड़ रुपये हो चुका है। इसमें कृषि का बजट भी लगातार बढ़ रहा है और जो दूसरे मंत्रालयों के बजट हैं, उनको इसमें इनक्लूड नहीं किया गया है। इसमें फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री का बजट अलग से है, कृषि के लिए उसमें पैसे दिये हैं, एमएसएमई की 'स्फूर्ति स्कीम' का भी बजट है। अगर इन सबको मिला दिया जाए और इसके अंदर इन्होंने नेबरिंग देशों के जो आंकड़े दिये हैं, उस पर मैं बताना चाहूंगा कि जैसे मलावी देश है, वहां की टोटल जनसंख्या दो करोड़ के आस-पास है और माले की जनसंख्या भी दो करोड़ के आस-पास है, नेपाल की जनसंख्या लगभग तीन करोड़ के आस-पास है, अगर उनके बजट को देखा जाए, तो उनके बजट की परसेंटेज सात, आठ और नौ परसेंट है। हमारे देश के अंदर जो हमारा कृषि का बजट है, वह लगभग 17 परसेंट के आस-पास है, जो पूरा बजट कृषि के लिए एलोकेटेड है। इसके

अलावा विश्व के जो दस बड़े देश हैं, उन टॉप 10 देशों के अंदर भारत के बजट का नाम निश्चित रूप से आ रहा है।

इसके अलावा माननीय सदस्य ने जो तेलंगाना राज्य के लिए फंड की बात कही है, मैं बताना चाहता हूं कि इसमें सेस ढाई परसेंट है, उस सेस का ढाई परसेंट का जो पैसा है, इसमें एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड के तौर पर माननीय प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी ने डेढ़ लाख करोड़ रुपये का प्रावधान कृषि के लिए किया है, जिसमें फिशरीज़ के लिए भी है और इसके अतिरिक्त एक लाख करोड़ रुपये का एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड है। अगर ये अपने राज्य के लिए इस फंड के तहत प्रपोज़ल लाते, जिसमें कोई भी व्यक्ति अगर किसान है, तो वह इसका फायदा ले सकता है, जिसमें तीन परसेंट ब्याज की छूट है और इसमें दो करोड़ रुपये तक उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा स्टेट का भी इस फंड के अंदर जो हिस्सा है, उस हिस्से के अनुसार भी उन्हें 2021-22 में 15,985 करोड़ रुपये उनका हिस्सा मिला है। इसलिए मुझे लगता है कि इनके पहले प्रश्न का हमने सीधा जवाब दिया है, हमने बजट को बढ़ाया है और मोदी जी की सरकार लगातार किसानों के कल्याण के लिए काम कर रही है।

SHRI K.R. SURESH REDDY: Sir, even for my first supplementary, I did not get the reply. My first supplementary was about oil palm. Nevertheless, as regards the second supplementary, the hon. Minister, again, while replying to my query, has said that almost about 17 per cent of the budget is given to agriculture. If you see the budget, it is only 3.1 per cent, and when you compare it with 2013 to now, they say that there has been five times increase. But in real terms, keeping the inflation in view, it is hardly one or one-and-a-half times more than the earlier budgets. So, my very specific question is that the Government is collecting Agriculture Cess on every litre of diesel or petrol sold and the amount is accumulated with the Government of India. Is there any rationale for distribution of the same to various States?

श्री कैलाश चौधरी : सर, यह प्रश्न कृषि मंत्रालय से संबंधित है, लेकिन माननीय सदस्य का प्रश्न कृषि मंत्रालय से संबंधित नहीं है, बल्कि उनका प्रश्न वित्त मंत्रालय से संबंधित है। इसके बावजूद भी मेरा यह कहना है कि एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड अभी प्रारंभ किया गया है। पहले यह फंड भी नहीं था। इसको कोरोना के समय में प्रारंभ किया गया है। जब से सेस देने की बात हुई है, पेट्रोलियम पर सेस देने की बात की गई है, उसके बाद से लगातार भारत सरकार के द्वारा राज्यों को भी इसका हिस्सा मिलता है। जो डेढ़ लाख करोड़ रुपए का एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड है, उसके तहत जो भी राज्य डिमांड करता है या किसान या कोई भी स्टार्ट अप इस फंड का उपयोग करना चाहता है, चाहे वह किसी भी राज्य का हो, इसके अंदर उसको फंड देने का प्रावधान किया गया है। आज देश का किसान इसका लाभ ले रहा है।

इन्होंने तेलंगाना के विषय में बात की है। इस संबंध में मैं यह बताना चाहता हूँ कि तेलंगाना के अंदर भी सौ से अधिक एफपीओज़ बने, उनके लिए भी एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत फंड देने का प्रावधान किया गया और इसके अंतर्गत फंड लिया भी है। यह 799 कोऑपरेटिव

सोसाइटीज़ में भी गया है और एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर के लगभग 581 प्रोजेक्ट्स शुरू हुए हैं। ये तेलंगाना के अंदर ही शुरू हुए हैं। इसलिए मुझे लगता है कि तेलंगाना हो या देश का कोई भी राज्य हो, वह लगातार इस योजना का लाभ ले रहा है।

SHRI TIRUCHI SIVA: Sir, India is basically an agricultural country. I am very happy that 'Agriculture' still remains as a State Subject. Otherwise, it would have been something like many other things, like 'Education' is now in the Concurrent List. I said this because the reply starts with, "Though Agriculture is a State Subject..." I don't know as to why the word 'though' has come here?
MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please put the question.

SHRI TIRUCHI SIVA: Tamil Nadu is only one of the States in the whole country which has presented a Budget exclusively for agriculture. So, the States are doing good, but what the Union Government is doing is a question. My simple question is: Has the Government got any plans to increase the MSP to 200 per cent of the production cost of the farmers?

श्री कैलाश चौधरी : माननीय उपसभापति जी, अभी एक कमेटी का गठन किया गया है, जो डायवर्सिफिकेशन, नेचुरल फार्मिंग और एमएसपी के विषय से संबंधित है, जिसमें किसान प्रतिनिधि भी होंगे, राज्य सरकारों के भी प्रतिनिधि होंगे, सेन्ट्रल गवर्नमेंट के भी अधिकारी होंगे। यह कमेटी आने वाले समय में इस पर विचार करेगी कि एमएसपी को किस प्रकार से और स्ट्रेंथेन किया जाए, किसान एमएसपी का अधिक लाभ कैसे ले सके। कमेटी इसके ऊपर जो निर्णय करेगी, उसके बाद उसके ऊपर विचार किया जाएगा।...**(व्यवधान)**...

श्री राघव चड्ढा : सर...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति : नहीं, नहीं, कृपया आप बैठिए।...**(व्यवधान)**... माननीय वि. विजयसाई रेड्डी जी।...**(व्यवधान)**...

श्री राघव चड्ढा : सर...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति : नहीं, नहीं। चड्ढा जी, आपकी कोई बात रिकॉर्ड पर नहीं जा रही है। आप ऐसे बीच में नहीं बोल सकते हैं।...**(व्यवधान)**...

श्री राघव चड्ढा : *

---

* Not Recorded

श्री उपसभापति : प्लीज़, नो...(**व्यवधान**)... वि. विजयसाई रेड्डी जी।...(**व्यवधान**)... Nothing is going on record. ...*(Interruptions)*... कृपया आप बोलें।...(**व्यवधान**)... Shri V. Vijayasai Reddy, please put your question. ...*(Interruptions)*...

श्री राघव चड्ढा : *

श्री संजय सिंह : *

श्री उपसभापति : आप दोनों की कोई बात रिकॉर्ड पर नहीं जा रही है। आप अनऑथराइज़ रूप से खड़े होकर बोल रहे हैं।...(**व्यवधान**)... Let it be recorded. ...*(Interruptions)*... आप दोनों चेयर की अनुमति के बगैर बोल रहे हैं, इसलिए आपकी बात रिकॉर्ड पर नहीं जाएगी।...(**व्यवधान**)...

श्री राघव चड्ढा : *

श्री संजय सिंह : *

श्री उपसभापति : विजयसाई रेड्डी जी, कृपया आप बोलें।...(**व्यवधान**)... आप प्रश्न पूछिए। Put your question.

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: Sir, the Department of Agricultural Research and Education has been allotted Rs.8,514 crores in the Revised Budget of 2021-22, and in the subsequent year 2022-23 also, the amount remains the same. With the increase in the extent of problems in agriculture and also in view of the fact that there is a global warming and problems in agriculture are increasing day by day, like climate change, etc., what does the Government intend to do? Will the Budgetary allocation for the Agricultural Research and Education be increased further or not?

श्री कैलाश चौधरी : माननीय उपसभापति महोदय, यह सवाल अच्छा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देश में कृषि का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है और साइंटिस्टों ने भी अच्छा काम किया है। इसके साथ ही, जो हमारे इंस्टिट्यूट्स हैं, जो हमारे कृषि विज्ञान केन्द्र हैं, उनके प्रति किसानों में एक जागरूकता भी आई है। मुझे इसमें यही कहना है कि कृषि का बजट लगातार बढ़ाया गया है और जो आईसीएआर का बजट है, उन्हें जैसी-जैसी आवश्यकता होती है,

---

* Not Recorded

उसके अनुसार उनका प्रपोज़ल आता है और उस प्रपोज़ल के अनुसार बजट बढ़ाना है, तो उसे बढ़ाया जाता है। आईसीएआर के हमारे रिसर्च सेंटर्स हैं, तो उनके लिए बजट है। उनकी हर साल एक मीटिंग होती है, उसमें जैसे भी आवश्यकता होती है, उसे उसके अनुसार बढ़ाने का काम किया जा रहा है। मुझे लगता है कि अगर आईसीएआर का बजट बढ़ाने की आवश्यकता होगी, तो भारत सरकार बढ़ाएगी। भारत सरकार हमेशा किसानों के लिए समर्पित रही है। निश्चित रूप से, यह उसी का परिणाम है कि भारत सरकार ने पिछले सात साल के अंदर रिसर्च के द्वारा 1,957 नई वेरायटीज़ निकाली हैं, जिनमें से 286 क्लाइमेट रिज़िल्येन्ट वेरायटीज़ हैं। ये वेरायटीज़ किसानों के खेत तक पहुंची हैं, जिनकी वजह से उत्पादन और उत्पादकता बढ़ी है। मुझे लगता है कि जैसी आवश्यकता होती है, उसके अनुसार बजट का प्रावधान किया जाता है।

SHRI SANDOSH KUMAR P: Sir, in this country, around 56 per cent of the agriculturists are landless, and, moreover, around 2,500 farmers committed suicide last year. You have mentioned about a lot of schemes. My question is: Do you have any special programme or scheme to address this problem?

श्री कैलाश चौधरी : माननीय उपसभापति महोदय, यह मैंने पहले भी कहा कि कृषि और किसानों के कल्याण के लिए भारत सरकार हमेशा समर्पित रही है और इसके लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं प्रारंभ की गई हैं। आज किसानों के लिए 'किसान सम्मान निधि योजना' प्रारंभ की गई है, जिसमें प्रत्येक किसान को चार महीने के अंदर दो हज़ार रुपये डायरेक्ट बेनफिट के तौर पर मिलते हैं। आज किसानों के अकाउंट में लगभग दो लाख करोड़ रुपये सीधे पहुंचे हैं। दस हज़ार एफपीओज़ बनाये जा रहे हैं और 5,000 से अधिक एफपीओज़ का तो रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है। इसके साथ ही, एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड भी है और एमएसपी के ऊपर खरीद भी की जा रही है, बल्कि रिकॉर्ड खरीद की जा रही है। अतः निश्चित रूप से, भारत सरकार प्रयास कर रही है। कृषि के क्षेत्र में राज्य सरकार की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर किसी प्रदेश में आपदा आती है, तब भारत सरकार उस स्टेट को हमारा स्टेट डिज़ास्टर फंड प्रारंभ में ही अवेलेबल करा देती है, ताकि अगर कोई आपदा आती है या ऐसी परिस्थिति बनती है, तो स्टेट स्वतः ही संज्ञान लेकर किसान को फंड अवेलेबल करा सके। इसके बावजूद भी, अगर स्टेट के पास पैसे का अभाव रहता है, वह फंड खत्म हो जाता है, तो वह भारत सरकार से नेशनल डिज़ास्टर फंड के लिए रिकमंडेशन कर सकती है।

श्री उपसभापति : प्रश्न संख्या 215.

*215. ***[The questioner was absent.]***